RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 09 SEPTEMBER TO 15 SEPTEMBER 2020 प्रति बुधवार वर्ष 06 अंक 3 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

रिलायंस ने अपने तेल-से-रसायन कारोबार को अलग करने की योजना का ब्योरा जारी किया Page 2

किसानों के लिए खुशखबरी 9 राज्यों में बनाए जाएंगे 22 बम्बू क्लस्टर Page 3

रेटिंग एजेंसियों ने अर्थव्यवस्था पर दी एक और टेंशन, 15 फीसदी तक गिरावट का अनुमान Page 5

editoria!

ईपीएफ पर नेगेटिव रिटर्न से उठे सवाल

एम्प्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) के निवेश संबंधी फैसले इधर कर्मचारियों की चिंता बढ़ाने लगे हैं। खबर है कि ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) के जरिए पिछले पांच साल से किए जा रहे निवेश का रिटर्न ईपीएफओ के लिए नेगेटिव में आया है। इस साल 31 मार्च की स्थिति के मुताबिक 1.03 लाख करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश पर कुल मिला कर माइनस 8.3 फीसदी रिटर्न है जबकि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के ईटीएफ पर माइनस 24.36 फीसदी। ईटीएफ किसी म्युचुअल फंड जैसा ही एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है, जिसकी खासियत यह है कि उसे कभी भी बेचा-खरीदा जा सकता है। ईपीएफओ अपनी सालाना जमा रकम का 85 फीसदी डेट इंस्ट्रूमेंट्स (बॉन्ड्स, डिबेंचर, प्रॉमिसरी नोट आदि) में निवेश करता है जबकि 15 फीसदी ईटीएफ के जरिए इक्विटी निवेश यानी शेयर खरीदने में लगाता है। इक्विटी निवेश आम तौर पर ज्यादा जोखिम वाला होता है लेकिन जोखिम ज्यादा होने के कारण उसमें रिटर्न भी ज्यादा होने की उम्मीद की जाती है। इस बार महामारी के चलते डेट इंस्ट्रूमेंट्स का प्रदर्शन खराब रहने का अंदेशा था तो ईटीएफ से बेहतर रिटर्न स्थिति को संभाल सकता था। मगर उसका हाल तो और भी बुरा निकला। यहां मामला ईटीएफ के चयन का भी है। सवाल उठ रहा है कि जिन ईटीएफ को चुना गया वे सही थे या नहीं, लेकिन बड़ी बहस इस बात को लेकर चली आ रही है कि आखिर लाखों कर्मचारियों की जीवन पर्यंत बचत को बाजार के जोखिम के अधीन कर देना कितना जायज है। पांच साल पहले जब यह फैसला किया गया था तब भी कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया था। तब यह दलील दी गई थी कि आज के जमाने में कोई भी निवेश बाजार के रिस्क से बाहर नहीं है। खुद कर्मचारी भी अपनी बचत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाजार में ही लगाते हैं। मगर कोई व्यक्ति सारी सूचनाएं जुटाकर उस आधार पर सोचे-समझे ढंग से अपने पैसे का निवेश करे, इसमें और लाखों कर्मचारियों की मेहनत की कमाई उनसे राय-मशविरा किए बगैर बाजार में झोंक देने में बुनियादी अंदर होता है। बहरहाल, नेगेटिव रिटर्न की यह खबर न केवल निकट भविष्य में रिटायर होने वाले बल्कि तमाम कर्मचारियों को बेचैन कर सकती है। भारत की निरंतर बढ़ती अर्थव्यवस्था में नेगेटिव ग्रोथ एक बिल्कुल नई चीज है। इसी तरह नेगेटिव रिटर्न भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे लोग परिचित हों और उसे सहजता से स्वीकार कर लें। हां, बैंकों के डूबने की खबरों से वे परिचित हैं और मेहनत की कमाई एक झटके में गायब हो जाने की मर्मांतक पीड़ा को समझ सकते हैं। पीएफ तो ऐसी निधि है जिस पर बुढ़ापे की पूरी आस टिकी रहती है। स्वाभाविक है कि ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड की अगले हफ्ते होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें लगी होंगी। अच्छा होगा कि सरकार अपनी तरफ से पहल करके कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाए कि ईपीएफ में आया पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और निवेश संबंधी फैसलों की आंच आम कर्मचारियों तक नहीं पहुंचने दी जाएगी।

कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट

सितंबर में 16 फीसदी टूटा WTI क्रूड

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस का कहर गहराने से कच्चे तेल (Crude Rate Today) के दाम में भारी गिरावट आई है। बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव 40 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जो कि जून के बाद का सबसे निचला स्तर है। वहीं, अमेरिकी लाइट क्रूड डब्ल्यूटीआई की कीमत 36 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड में बुधवार को लगातार छठे दिन नरमी के साथ कारोबार चल रहा था। कोरोना का कहर दोबारा गहराने से दुनियाभर में आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले असर से तेल की खपत मांग में नरमी की आशंका के बीच कीमतों में गिरावट आई है।

सितंबर में अब तक डब्ल्यूटीआई का भाव 16 फीसदी से ज्यादा टूटा

बीते सत्र में ब्रेंट क्रूड पांच फीसदी से ज्यादा टूटा जबकि वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) का भाव छह फीसदी से ज्यादा लुढ़का। सितंबर में अब तक डब्ल्यूटीआई का भाव करीब सात डॉलर प्रति बैरल यानी 16 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है जबकि ब्रेंट का भाव 15 फीसदी से ज्यादा लुढ़का है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट से भारतीय वायदा बाजार में भी कच्चे तेल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार चल रहा था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर बुधवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे कच्चे तेल के सितंबर अनुबंध में पिछले सत्र से छह रुपये की नरमी के साथ 2,699 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था जबकि बीते सत्र में एमसीएक्स पर कच्चे तेल के दाम में साढ़े छह फीसदी से ज्यादा की गिरावट रही। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का दाम 15 जून के बाद के सबसे निचले स्तर पर है।

कोरोना महामारी के चलते मांग कम होने की आशंका से कीमतों में गिरावटः अनुज गुप्ता

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटर कांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर ब्रेंट क्रूड के नवंबर डिलीवरी अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 0.20 फीसदी की कमजोरी के साथ 39.70 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड का भाव 39.36 डॉलर प्रति बैरल तक टूटा। वहीं, डब्ल्यूटीआई के अक्टूबर डिलीवरी वायदा अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 0.27 फीसदी गिरावट के साथ 36.66 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले कारोबार के दौरान डब्ल्यूटीआई का भाव 36.17 डॉलर प्रति बैरल तक टूटा। एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसीडेंट (एनर्जी व करेंसी) अनुज गुप्ता ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते तेल की मांग में नरमी रहने की आशंका से कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डॉलर में मजबूती आई है और सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको ने एशियाई देशों में तेल की बिक्री बढ़ाने के लिए कीमतों में कटौती की है, वहीं अमेरिका में तेल की मांग कमजोर है। उन्होंने बताया कि तेल की मांग नरम रहने और डॉलर में मजबूती से बीते एक सप्ताह में डब्ल्यूटीआई के दाम में करीब 16 फीसदी की गिरावट आई है। बता दें कि जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 2.75 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं इस बीमारी से अब तक 8.97 लाख लोगों की जान जा चुकी है। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) के ताजा अपडेट के अनुसार, बुधवार की सुबह तक 27,570,742 मामले और 8,97,383 मौतें दर्ज हो चुकी थीं।

कोरोना काल में कंपनियों को बड़ी राहत
सरकार ने किया यह अहम काम

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में कंपनियों को 2019-20 वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) करने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का समय दे दिया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक मंत्रालय ने इस बारे में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को आदेश जारी करने को कहा है। आरओसी से कहा गया है कि वह इस संबंध में औपचारिक तौर पर आवेदन करने और फीस का भुगतान किए बिना ही एजीएम करने की समयसीमा विस्तार का आदेश जारी करे। विज्ञप्ति में कहा गया है, 'इस संबंध में चाहे आवेदन पहले दिया जा चुका है और उसे मंजूरी नहीं मिली है अथवा खारिज किया गया है, ऐसे आवेदन भी राहत पाने के दायरे में होंगे।' कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का काम कंपनी कानून के अमल पर ध्यान देना है। मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, करीब 12 लाख कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है।

एजीएम की समयसीमा बढ़ाने की मांग

कंपनियों को उनकी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की समय सीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। कंपनियों को यह राहत कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न संघों और संगठनों ने कंपनियों के लिए एजीएम करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी।

पटरी पर लौटने लगी है रेलवे की मालढुलाई, सितंबर में 11 फीसदी बढ़ी फ्रेट लोडिंग

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने इस महीने 6 सितंबर तक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत अधिक मालढुलाई की है। रेलवे की इससे हुई आय भी पिछले साल के आंकड़े को पार कर गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि 6 सितंबर तक भारतीय रेल ने 1.92 करोड़ टन मालढुलाई की। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 1.74 करोड़ टन की मालढुलाई से 10.41 प्रतिशत यानी 18.1 लाख टन अधिक है। इस दौरान रेलवे ने मालढुलाई से 1,836.15 करोड़ रुपये कमाए जो पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई आय 1,706.47 करोड़ रुपये से 129.68 करोड़ रुपये अधिक है। बयान के मुताबिक छह सितंबर 2020 तक रेलवे ने 81.1 लाख टन कोयला, 25.9 लाख टन लौह अयस्क, 12 लाख टन खाद्यान्न, 10.3 लाख टन उर्वरक और 10.5 लाख टन (क्लिंकर को छोड़कर) सीमेंट की मालढुलाई की।

पावर ग्रिड को संपत्ति मौद्रीकरण की मंजूरी, पहली खेप में 7,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को उसकी अनुषंगी कंपनियों की संपत्तियों के मौद्रीकरण की अनुमति दे दी। यह बिक्री अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के जरिये की जायेगी। इससे कंपनी को पहली खेप में 7,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने एक अहम् निर्णय लेते हुये पावर ग्रिड कार्पोरेशन को अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) के जरिये संपत्तियों का मौद्रीकरण करने को मंजूरी दे दी। एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। यह पहला मौका होगा जब बिजली क्षेत्र का कोई सार्वजनिक उपक्रम अपनी परिसंपत्तियों को इनविट प्रणाली के जरिये मौद्रीकरण करेगा और उससे प्राप्त राशि का नये और निर्माणाधीन पूंजीगत परियोजनाओं में इस्तेमाल करेगा। इससे पावर ग्रिड को पहले खेप में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्राप्त हो सकती है। पावर ग्रिड की इन परिसंपत्तियों में उच्च क्षमता की ट्रासमिशन लाइनें और सब- स्टेशन शामिल हैं। ये संपत्तियां विशेष उद्देशीय निकाय (एसपीवी) के रूप में पावर ग्रिड के तहत हैं। इस तरह से प्राप्त राशि का इस्तेमाल पावर ग्रिड अपनी नई परियोजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं में कर सकेगा। विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाली पावर ग्रिड कार्पोरेशन एक सार्वजनिक उपक्रम है जो कि विद्युत पारेषण के क्षेत्र में कारोबार करती है। कंपनी का पूरे देश में फैला ट्रांसमिशन नेटवर्क है।

रिलायंस ने अपने तेल-से-रसायन कारोबार को अलग करने की योजना का ब्योरा जारी किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तेल से रसायन (ओ2सी) कारोबार वाली नयी इकाई में तेल रिफाइनरी और पेट्रो रसायन संपत्तियों के साथ ही ईंधन का खुदरा कारोबार शामिल होगा। लेकि केजी- डी6 जैसे तेल गैस खोज एवं उत्पादन क्षेत्रों और कपड़ा कारोबार को इससे अलग रखने की योजना है। समूह के कारोबार को अलग-अलग करने के बारे में कंपनी ने यह जानकारी दी है। रिलायंस इडस्ट्रीज ने अपने ओ2सी कारोबार को अलग करने को लेकर काम शुरू कर दिया है। इस कारोबार में संभवतः सउदी अरब की कंपनी सउदी अरामको को हिस्सेदार बनाया जा सकता है। रिलायंस ओ2सी लिमिटेड में तेल रिफाइनिंग और पेट्रो रसायन संयंत्र तथा विनिर्माण परिसंपत्तियां, थोक ईंधन विपणन कारोबार के साथ ही ब्रिटेन की बीपी के साथ खुदरा ईंधन संयुक्त उद्यम में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला कारोबार शामिल होगा। रिलायंस का सिंगापुर

और ब्रिटेन स्थित तेल व्यापार करने वाली अनुषंगी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊरुग्वे पेट्रोक्यूमिका एसए भी ओ2सी इकाई की छतरी के नीचे रखी जाएंगी। रिलायंस का पाइपलाइन कारोबार भी इसी कंपनी के अंतर्गत आएगा। वहीं रिलायंस के सीबीएम ब्लॉक से कोल बेड मीथेन को आगे पहुंचाने वाली इथेन गैस पाइपलाइन, विदेशों में तेल एवं गैस संपत्तियों की मालिक रिलायंस इंडस्ट्रीज (मिडल ईस्ट) डीएमसीसी और घरेलू तेल खोज एवं उत्पादन परिसंपत्तियों रिलायंस के ओ2सी इकाई का हिस्सा नहीं होंगी। रिलायंस के नरोदा के बाहर से चल रहा का कपड़ा कारोबार, क्रिकेट स्टेडियम सहित बड़ोदा टाउनशिप और जमीन, जामनगर विद्युत कारखाना और सिक्का पोर्ट्स एण्ड टर्मिनल्स लिमिटेड भी रिलायंस ओ2सी का हिस्सा नहीं होंगी। रिलायंस इंडस्ट्रील लिमिटेड ने ओ2सी कारोबार का मूल्यांकन 75 अरब डालर किया है और वह इसमें 20 प्रतिशत हिस्सेदारी सउदी अरब आयल कंपनी (अरामको) को बेचने पर बातचीत कर रही है। कंपनी ने कहा है कि वह ओ2सी कारोबार में रणनीतिक और अन्य निवेशकों को लाने की विभिन्न संभावनाओं को तलाश रही है।

सिपेट भागलपुर, वाराणसी में स्थापित करेगी दो नए कौशल केंद्र

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) बिहार के भागलपुर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जल्द ही अपने दो कौशल विकास केंद्र खोलेगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सिपेट, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है। रसायन और पेट्रोरसायन सचिव आर. के. चतुर्वेदी ने कहा कि इन केंद्रों में हर साल 1,000 युवाओं को पेट्रोरसायन और उससे जुड़े अन्य उद्योगों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र तकनीकी सहायता सेवा क्षेत्र में नए और मौजूदा उद्योगों के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे। पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान में 'सिपेट' के 43 केंद्र काम कर रहे हैं और नौ अन्य खुलने की प्रक्रिया में हैं। वर्तमान में सिपेट पॉलिमर विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 31 केंद्रों के माध्यम से डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। 'सिपेट' स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी कार्यक्रमों में भी योगदान दे रहा है।

शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 171 अंक गिरा

मुम्बई। आईपीटी नेटवर्क

बुधवार यानी 9 सितंबर 2020 को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। जहां सेंसेक्स करीब 171.43 अंक की गिरावट के साथ 38193.92 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 39.40 अंक की गिरावट के साथ 11278.00 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा आज बीएसई में कुल 2830 कंपिनयों में ट्रेडिंग हुई, इसमें से करीब 838 शेयर तेजी के साथ और 1835 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं 157 कंपनियों के शेयर के दाम में कोई अंतर नहीं आया। वहीं आज शाम को डॉलर के खिलाफ रुपया 6 पैसे की मजबूती के साथ 73.53 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।

जियो के बाद अब रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ का निवेश करेगा सिल्वर लेक

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक 1.75% इक्विटी के लिए 7 हजार 500 करोड़ रू का निवेश करेगा। इस सौदे में रिलायंस रिटेल की प्री-मनी इक्विटी मूल्य 4.21 लाख करोड़ रू आंका गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश के बाद सिल्वर लेक अब रिलायंस रिटेल में भी निवेश कर रहा है। सिल्वर लेक को दुनिया में टेक्नॉलोजी सेक्टर के सबसे बड़े निवेशकों में माना जाता है। सिल्वर लेक का रिलायंस रिटेल में निवेश करना इस बात का साफ संकेत है कि रिलायंस रिटेल भारतीय रिटेल सेक्टर में बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरा है। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किया था।

सिल्वर लेक इससे पहले, 1.35 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,200 करोड़ रू से अधिक का निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स में कर चुका है। रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स का कुल वैल्यूएशन 9 लाख करोड़ रू पार कर गया है। देश के अनेकों शहरों में फैले रिलायंस रिटेल के 12 हजार से अधिक स्टोर्स में करीब 64 करोड़ का फुटफॉल प्रतिवर्ष हैं। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने इस नेटवर्क से 3 करोड़ किराना स्टोर्स और 12 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने हाल ही में जियोमार्ट को भी लॉन्च किया है जो ग्रोसरी सेक्टर का ऑनलाइन स्टोर है। जियोमार्ट पर हर दिन करीब 4 लाख ऑर्डर बुक हो रहे हैं।

सिल्वर लेक डील पर खुशी जाहिर करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा, 'हमें खुशी है कि लाखों छोटे व्यापारियों के साथ साझेदारी करने के हमारे परिवर्तनकारी विचार से सिल्वर लेक अपने निवेश के माध्यम से जुड़ा है। भारतीय रिटेल सेक्टर में भारतीय उपभोक्ताओं को मूल्य आधारित सर्विस मिले यही हमारा प्रयास है। हमारा मानना है कि प्रौद्योगिकी रिटेल क्षेत्र में जरूरी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण साबित होगी और रिटेल इको सिस्टम से जुड़े सभी घटक एक बेहतर विकास प्लेटफार्मों का निर्माण कर सकेंगे। भारतीय रिटेल सेक्टर में हमारे विजन को आगे बढ़ाने में सिल्वर लेक महत्वपूर्ण भागीदार होगा'

निवेश पर टिप्पणी करते हुए, सिल्वर लेक के सह-सीईओ और प्रबंध साझेदार, श्री एगॉन डरबन ने कहा, 'मुकेश अंबानी और रिलायंस की टीम ने अपने प्रयासों से रिटेल और टेकनॉलोजी सेक्टर में लीडरशिप हासिल की है। इतने कम समय में जियोमार्ट की सफलता, विशेषकर तब जबकि भारत बाकी दुनिया के साथ कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, वास्तव में अभूतपूर्व है।

सीएचडी कैमिकल्स का लाभ 80% तक बढ़ा मिला 56 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट ऑर्डर

चंडीगढ़। आईपीटी नेटवर्क

बीएसई में सूचीबद्ध, कैमिकल्स व डाई की मेन्युफेक्चरिंग, ट्रेडिंग और वितरक कम्पनी, सीएचडी कैमिकल्स लिमिटेड ने 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए बेहतरीन अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों की घोषणा की, जहां कंपनी का कारोबार 4.74 करोड़ रूपए पहुँच गया है और लाभ में 80% की वृद्धि हुई है जो 12.84 लाख रूपए (Q119-20) से 22.96 लाख रूपए (Q120-21) हो गया है। ईपीएस 0.12 लाख रूपए (Q1 19-20) से 0.23 लाख रूपए (Q1 20-21) लगभग दोगुना हो गया। कंपनी ने हाल ही में घोषणा की थी कि उसे 56 करोड़ रूपए का निर्यात ऑर्डर मिला था। कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया के पूरे क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार कर रही है और इसी उद्देश्य से कंपनी ने उसी क्षेत्र के अग्रणी समूह के साथ संघों का गठन किया है। यह आदेश कंपनी का गेमचेंजर हो सकता है। यह विशाल आदेश कंपनी को ग्लोबल मार्केट में अपने पैर के आधार को स्थापित करने में मदद करेगा और कारोबार बढ़ाने के साथ-साथ लाभप्रदता में भी मदद करेगा।

कम्पनी, उत्पादों की एक विस्तृत रेंज की पेशकश करती है, जिसमें ऑक्ज़ीलरीज़ (सेना से सम्बंधित): डाइंग (रंग से सम्बंधित); इज़ी केयर फिनिशिंग; फिनिशिंग; फ्लेम रिटारडेन्ट; ऑक्ज़ीलरी ज़ः ऑप्टिकल ब्राइटनर; पिग्मेंट प्रिंटिंग; वाटर रेपलेंट; एसिड डाई; डायरेक्ट डाई; डिजिटल प्रिंटिंग के लिए स्याही; वेट डाई; एन्टीफोमिंग डिटरजेंट तथा बेसिक कैमिकल्स शामिल हैं। कम्पनी के पास वर्तमान में स्वयं का अत्याधुनिक आर एंड डी (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) केंद्र है। जिसमें अल्ट्रा मॉर्डन उपकरण शामिल हैं जो फार्मास्युटिकल एपीआईज़, कैमिकल्स आदि के लिए आर एंड डी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे कम्पनी की आर एंड डी क्षमता दुगुनी हो जाएगी। इसके साथ ही नये एवम किफायती उत्पादों को विकसित करने तथा रासायनिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने सहित उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने एवं मौजूद उत्पादों की पैदावार को बढ़ाने, डाउनस्ट्रीम (निचले स्तर के) उत्पादों के लिए एकीकरण की ओर बढ़ने, आदि जैसे लाभदायक अवसर भी अधिक हो जाएंगे। बाज़ार के विश्लेषण के अनुसार, इस विस्तार की वजह से कम्पनी के टर्नओवर तथा लाभप्रदता के मजबूती से बढ़ने की आशा है।

बांस उद्योग और किसानों को मिलेगी अलग पहचान, 9 राज्यों में बनाए जाएंगे 22 बम्बू क्लस्टर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार तमाम छोटे-बड़े उद्योग, खेती-बाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए की योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है. उद्योग-धंधों और किसानों की आमदनी से जुड़ी एक योजना है राष्ट्रीय बांस मिशन। सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग-धंधों को गति देने पर फोकस कर रही है। इस कड़ी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नौ राज्यों में 22 बांस क्लस्टर (bamboo clusters) शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि देश अब बांस उत्पादों (bamboo products) के निर्यात को बढ़ाने के लिए कमर कस रहा है। बांस के क्लस्टर की स्थापना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 'लोगो' यानी प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। राष्ट्रीय बांस मिशन का लोगो तैयार करने के

लिए mygov प्लेओटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। देशभर से मिली 2033 एंट्री में से तेलंगाना के साईं राम गौडी एडिगी ने जो डिजाइन तैयार किया था, उसे चुना गया और उन्हें नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

क्या कहता है लोगो

बांस मिशन के लोगो (NBM Logo) में बांस की छवि भारत के विभिन्न हिस्सों में बांस की खेती को चित्रित करती है। लोगो के चारों ओर औद्योगिक पहिया, बांस क्षेत्र के औद्योगीकरण के महत्व को दर्शाता है। लोगो में सुनहरे पीले व हरे रंग का संयोजन दर्शाता है कि बांस 'हरा सोना' (Green Gold) है। आधा औद्योगिक पहिया और आधा किसान सर्कल किसानों और उद्योग दोनों के लिए बांस के महत्व को दर्शाता है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि बांस की लोकर वैरायटी से स्थानीय कारीगरों को मिशन द्वारा दिया जा रहा समर्थन भी 'वोकल फॉर लोकल' (local for vocal) के लक्ष्य को साकार करेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी (Farmers Income) बढ़ाने और कुछ कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत में बांस की संपत्ति और बढ़ते उद्योग के साथ, भारत को इंजीनियर और दस्तकारी उत्पादों, दोनों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में खुद को स्थापित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 का संशोधन करके बांस को जंगल के पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया है।

पीएम मोदी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई-गोपाल ऐप

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई-गोपाल ऐप (e-Gopala App) के साथ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। PMMSY देश में मत्स्य पालन क्षेत्र पर केंद्रित और इसके सतत विकास की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-2025 के बीच 5 साल की अवधि के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है। इसमें से लगभग 12,340 करोड़ रुपये का निवेश समुद्री, आंतरिक मत्स्य पालन और अन्य मत्स्य पालन (Marine, Inland fisheries and Aquaculture) में लाभार्थियों के उन्मुख गतिविधियों के लिए प्रस्तावित है और लगभग 7,710 करोड़ रुपये का निवेश मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया जाना है।

उद्देश्य 55 लाख अन्य लोगों के लिए प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना

इसका उद्देश्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को अतिरिक्त 70 लाख टन बढ़ाना, 2024-25 तक मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को 1,00,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना, मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना, मछली उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को वर्तमान के 20-25ज्ञ से 10ज्ञ पर लाना और मत्स्य पालन क्षेत्र और इससे संबद्ध गतिविधियों में 55 लाख अन्य लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके अलावा ई-गोपाल ऐप किसानों के सीधे उपयोग के लिए तैयार किया गया एक व्यापक नस्ल सुधार बाज़ार और सूचना पोर्टल है।

ईपीएफ सदस्य की अचानक मौत पर नॉमिनी को मिलेगा अब इतना क्लेम

नई दिल्ली। कोरोना काल में देशभर के 4.5 करोड़ लोगों के परिवार के लिए राहत भरी खबर है। अब किसी भी ईपीएफ सदस्य की अचानक मौत पर नॉमिनी को इश्योरेंस के 7 तक लाख रुपये मिलेंगे। अभी 6 लाख रुपये तक ही दिए जाते थे। ईपीएफओ की पेंशन-ईडीएलआई कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पेंशन स्कीम 1995 की जगह नई स्कीम लाने की तैयारी शुरू की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारक की बीमारी, दुर्घटना, असामायिक या स्वाभाविक मौत पर 1976 से इम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस स्कीम शुरू कर रखी है। इस संबंध में ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्य हरभजन सिंह ने बताया कि पेंशन कमेटी ने नए फैसले को मंजूरी दे दी है। हाई पॉवर कमेटी गठित कर दी गई है। औपचारिक मुहर बुधवार को सीबीटी की बैठक में लगेगी। न्यूनतम इंश्योरेंस की धनराशि ढाई लाख ही रहेगी। हिन्दुस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनपीएस की तर्ज पर पीएफ सदस्यों के लिए नई पेंशन स्कीम लाई जा रही है। बोर्ड सदस्यों को एजेंडा दिया गया है पर प्रावधानों को साफ नहीं किया गया है इसलिए सोमवार को हुई पेंशन-ईडीएलआई कमेटी में सभी सदस्यों ने विरोध कर दिया। सदस्यों ने बैठक में पूछा कि बिना मांग के नई पेंशन स्कीम लाने का औचित्य क्या है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। फिर ईपीएफओ की नई पेंशन स्कीम समझ से परे है। सदस्यों ने ईपीएफओ की पेंशन स्कीम 1995 को ही मजबूत करने का सुझाव दिया है।इस तरह कर सकते बीमा राशि का दावा अंशधारक की अचानक मौत पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा राशि के लिए फार्म-5 भरकर क्लेम कर सकता है। नॉमिनी अगर माइनर है तो उसकी तरफ से गार्जियन क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और बैंक ब्योरा देना होगा। क्लेम के 30 दिन में भुगतान नहीं होने पर नॉमिनी को 12 फीसदी ब्याज अतिरिक्त मिलेगा।

सड़क दुर्घटना में कमी के लिए सरकारी-निजी भागीदारी में स्मार्ट यातायात प्रणाली की जरूरत : गडकरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में कारगर कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए लोक निजी भागीदारी मॉडल पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इसका मॉडल तैयार करने के लिए एक प्रतिष्ठित निजी सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 2019 लागू होने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है। भारत में सालाना पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है, जबकि करीब तीन लाख लोग अपंग हो जाते हैं। गैर-लाभकारी संस्था 'कंज्यूमर वॉयस' के सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, " यह समय है जब हमें परिवहन में लोक निजी

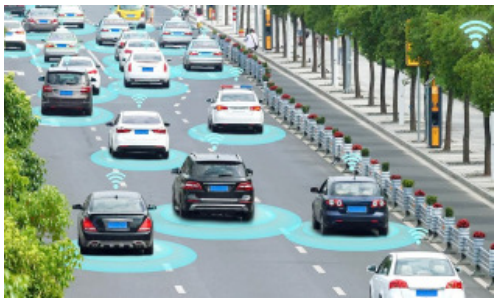

भागीदारी मॉडल को अपनाना चाहिए। हम एक निजी सलाहकार या कहें एक प्रतिष्ठित कंपनी को नियुक्त करेंगे जो अध्ययन कर बताएगी कि कैसे परिवहन क्षेत्र में लोक निजी भागीदारी मॉडल को लाया जा सकता है। वह राज्य, नगर निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर पर बेहतर समन्वय वाली एक कुशल यातायात प्रणाली (आईटीएस) के मॉडल को लेकर विशेष तौर पर सुझाव देगी।" उन्होंने कहा कि इसकी निविदा बहुत जल्द निकाली जाएगी। कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली में केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चुंगी कर वसूलने की व्यवस्था के साथ-साथ सीसीटीवी, मौसम निगरानी, कई तरह के संदेश साइनबोर्ड, उन्नत संचार प्रणाली, ट्रैफिक प्रबंधन और अन्य डिजिटल सेवाएं शामिल हैं। गडकरी ने विश्वास जताया कि सड़क सुरक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और पहलों से 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में 50 प्रतिशत तक कमी आएगी।

फैक्टरियों का 70 फीसदी काम पटरी पर, प्रवासी मजदूर भी लौटे

नई दिल्ली। एजेंसी

लॉकडाउन के दौरान ठप पड़ी फैक्टरियों में तकरीबन 70 फीसदी कामकाज पटरी पर लौट चुका है। वहीं, अनलॉक-4 में मिली ढील से कारोबारियों को अब आर्थिक गतिविधियों में और सुधार की उम्मीद है। कोरोना काल में गांवों को पलायन करने वाले अधिकांश मजदूर और कारीगर भी वापस फैक्टरियों में अपने काम पर लौट चुके हैं। हालांकि कारोबारी बताते हैं कि सप्लाई चेन दुरुस्त नहीं होने से फैक्टरियों में कच्चे माल की आपूर्ति अभी सही तरीके से नहीं हो रही है।

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में जहां देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा पसरा था अब वहां चहल-पहल बढ़ गई है, लेकिन सभी सेक्टरों की फैक्टरियों की हालत अभी नहीं सुधरी हैं। कारोबारी संगठनों के मुताबिक, टेक्सटाइल्स, प्रिंटिंग, एडवरटाइजिंग समेत कई सेक्टरों के काम-काज में अभी सुस्ती बनी हुई है जिसकी मुख्य वजह कमजोर मांग है। ओखला चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अरुण पोपली ने कहा कि पैकेजिंग, इंजीनियरिंग और खाद्य-वस्तुओं से जुड़ी फैक्टरियों में तो कामकाज काफी सुधर गया है लेकिन प्रिंटिंग प्रेस, विज्ञापन जैसे कार्यों में अभी तक सुस्ती है।

60-70 फीसदी पटरी पर

उन्होंने कहा कि फैक्टरियों का काम-काज कुल मिलाकर 60-70 फीसदी पटरी पर लौट चुका है। पोपली ने कहा कि ऑर्डर भी तकरीबन 60 फीसदी आने लगे हैं। गांवों को पलायन कर चुके मजदूरों की वापसी के संबंध में उन्होंने कहा कि जो लौटने वाले मजदूर व कारीगर थे वे लौट चुके हैं, सिर्फ वही लोग नहीं लौटे हैं जिनको गांवों में ही काम मिल गया है। हालांकि इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी फैक्टरियों का काम-काज काफी सुधर गया है।

ग्रेटर नोएडा के कारोबारी और लघु उद्योग भारती से जुड़े अश्विनी महेंद्रू ने बताया कि नए ऑर्डर मिल रहे हैं लेकिन सप्लाई चेन दुरुस्त नहीं होने से कच्चे माल की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि कारीगर, कर्मचारी व मजदूर तकरीबन 95 फीसदी काम पर लौट चुके हैं। हालांकि टेक्सटाइल्स सेक्टर से जुड़े संगठन टेक्सटाइल्स प्रोसेसर्स एसोसिएशन, फरीदाबाद के जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि निर्यात मांग कमजोर होने के कारण काम-काज सुस्त है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोप से ऑर्डर अभी नहीं मिल रहे हैं और फैक्टरियों में मजदूर व कारीगर की भी अभी कमी बनी हुई है।

अनलॉक-4 में बढ़ी चहल-पहल

दिल्ली के मायापुरी इलाके में करीब 1100 फैक्टरियां हैं, जहां अनलॉक-4 में चहल-पहल बढ़ गई है। मायापुरी इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नीरज सहगल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर व कारीगर गांव चले गए थे उनमें से ज्यादातर लौट चुके हैं और फैक्टरियों का काम-काज भी तकरीबन 60-70 फीसदी पटरी पर लौट चुका है। उन्होंने कहा कि जो मजदूर अब तक नहीं लौटे हैं वो अभी लौटेंगे भी नहीं क्योंकि उनको गांवों में ही काम मिल गया है। उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष जनक कुमार भाटिया ने भी बताया कि अपेरल, गार्मेंट से जुड़े उद्योग में अभी मजदूरों और कारीगरों की कमी है, लेकिन आने वाले दिनों जैसे-जैसे गतिविधियां बढ़ेंगी और ऑर्डर मिलने लगेंगे और सप्लाई चेन दुरुस्त होगा मजदूर व कारीगर भी काम पर लौटने लगेंगे। भाटिया ने कहा, 'बारिश का सीजन भी अब आखिरी दौर में है और कोरोना महामारी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। जागरूकता बढ़ने से लोग सावधानी बरत रहे हैं लेकिन उनके मन में जो डर बैठा था वह अब कम होने लगा है। आगे त्योहारी सीजन है जिसमें नए ऑर्डर मिलने से काम-काज बढ़ने की उम्मीद है।'

रिलायंस जियो, वर्ल्डरीडर की साझेदारी, 'जियाफोन' के 15 करोड़ उपयोक्ताओं को बच्चों की किताबों तक पहुंच

नयी दिल्ली। एजेंसी

वैश्विक गैर-लाभकारी शैक्षिक संगठन वर्ल्डरीडर ने रिलायंस जियो के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इसके तहत रिलायंस जियो के 15 करोड़ 'जियोफोन' उपयोक्ताओं को बच्चों की किताबों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। छोटी उम्र के बच्चों पर शिक्षा की स्थिति की वार्षिक रपट-2019 के मुताबिक करीब 80 प्रतिशत भारतीय परिवारों के पास इसके लिए कोई पठन सामग्री नहीं है। वर्ल्डरीडर ने एक बयान में कहा, " जियोफोन पर वर्ल्डरीडर की 'बुकस्मार्ट' ऐप के माध्यम से इस साझेदारी के तहत 15 करोड़ से अधिक जियाफोन उपयोक्ताओं को बच्चों की किताबों तक मुफ्त पहुंच सुनिश्चित होगी। इनमें से अधिकांश कम संसाधनों वाले परिवार से आते हैं या पहली बार इंटरनेट का प्रयोग करने वालों में से हैं।" बुकस्मार्ट को जियोफोन के ऐप स्टोर में शिक्षा श्रेणी के तहत ढूंढा जा सकता है। बुकस्मार्ट अभिभावकों, देखभाल करने वालों और प्राइमरी के छात्रों को उम्र के आधार पर किताबों का वर्गीकरण कर बनाये गए पुस्तकालय तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। इस बारे में जियो के प्रवक्ता ने कहा कि वर्ल्डरीडर के साथ साझेदारी को लेकर हम रोमांचित है। यह कोविड-19 महामारी और नयी जीवनशैली के बीच देश के करोड़ों बच्चों को घर पर करोड़ों डिजिटल किताबों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए EPF पर दो किस्तों में मिलेगा ब्याज

जानिए खाते में कब आएगी कितनी रकम

नयी दिल्ली। एजेंसी

रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बुधवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5 फीसदी ब्याज निर्धारित किया है। सरकार हालांकि ब्याज का भुगतान दो किस्तों में करेगी. फिलहाल, EPFO की तरफ से सिर्फ 8.15 फीसदी ब्याज अक्टूबर में दिया जाएगा। शेष 0.35 फीसदी ब्याज का भुगतान दिसंबर माह में किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, ईपीएफओ ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया। इसका फायदा 6 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को होगा. यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 0.15 फीसदी कम है. वित्त वर्ष 2018-19 में EPF पर 8.65 फीसदी ब्याज दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि EPFO की निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी (CBT) की दिसंबर में दोबारा बैठक होगी, जिसमें सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में 0.35 फीसदी ब्याज ट्रांसफर करने पर फैसला किया जाएगा। यह मामला मीटिंग के एजेंडे में नहीं था, लेकिन बोर्ड के कुछ सदस्यों ने सब्सक्राइबर्स के खाते में ब्याज का पैसा जमा कराने में देरी का मसला उठाया।

इस साल मार्च में हुई मीटिंग में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में बोर्ड ने 2019-20 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज देने का फैसला किया था। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय बीते वित्त वर्ष के लिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को 8.5 फीसदी ब्याज देने पर अपनी मंजूरी पहले ही दे चुका है। इससे पहले ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में 8.5 फीसदी ब्याज के भुगतान पर घाटे की भरपाई के लिए ईटीएफ में अपने कुछ निवेश से पैसा निकालने की योजना बनाई थी। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते मार्केट की खराब स्थिति को देखते हुए यह योजना टाल दी गई।

क्या है PF का हिसाब-किताब?

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने वेतन और महंगाई भत्ते की 12 फीसदी रकम पीएफ खाते में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। इतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी अपनी तरफ से देती है। हालांकि, कंपनी का कंट्रीब्यूशन दो हिस्सों में जाता है. इसमें से 8.33 फीसदी रकम पेंशन स्कीम (EPS) में जाती है. वहीं, शेष 3.67 हिस्सा EPF खाते में जाता है।

सामूहिक सोच के साथ स्वच्छ ऊर्जा मिशन पर काम कर रहा है भारतः पीयूष गोयल

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक सामूहिक सोच के साथ स्वच्छ ऊर्जा मिशन पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा और नयी प्रौद्योगिकियां निश्चित रूप से हमारे भविष्य को बेहतर बनायेंगी तथा दुनिया को स्वच्छ व जीवन के लिये बेहतर स्थान बनाने में मदद करेंगी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) द्वारा आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए आठ सितंबर को ये टिप्पणियां कीं। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को इसकी जानकारी दी गयी। गोयल ने कहा, 'स्वच्छ ऊर्जा के साथ भारत के जुड़ाव के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक सामूहिक सोच के साथ काम कर रहे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग काम करने संबंधी प्रक्रियाओं को समाप्त किया जा रहा है और भावी पीढ़ियों के स्वच्छ भविष्य के लिये हम एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'ऊर्जा के स्रोतों में शुद्धता के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सभी इसे पूरा करने में भाग लें और हमारे बच्चों के लिये बेहतर भविष्य सुरक्षित करें।" गोयल ने भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने के लिये धर्मेंद्र प्रधान के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गयी पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बदलाव और परिवर्तनकारी पहल, देश को जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर जाने में मदद करेंगे। कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करने के लिये पेरिस में सीओपी -21 शिखर सम्मेलन के निर्णय को कई वर्षों में लिया गया सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक निर्णय बताते हुए गोयल ने कहा, 'यह सभी के स्वच्छ भविष्य के लिये सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक निर्णय था। हमने दुनिया के स्वच्छ और बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने का फैसला किया था, यह तय किया था कि प्रत्येक देश कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिये क्या करेगा और हम सामूहिक रूप से इस बात पर सहमत हुए थे कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना सभी हितधारकों की वैश्विक जिम्मेदारी होगी।'

एक के बीमार होने के बाद एस्ट्राजेनेका कोविड- 19 टीके का अध्ययन अस्थाई तौर पर रुका

न्यूयार्क। एजेंसी

एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीके का अंतिम चरण का अध्ययन अस्थाई तौर पर रोक दिया गया है। कंपनी जांच कर रही है कि टीका लेने वाले एक व्यक्ति का बीमार होना कहीं टीके का साइड इफेक्ट तो नहीं है।

कंपनी ने मंगलवार शाम जारी एक वक्तव्य में कहा है, "टीके को लेकर उसकी मानक समीक्षा प्रक्रिया में फिलहाल ठहराव आया है, इस दौरान उसके सुरक्षा आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है।" एस्ट्राजेनेका ने हालांकि, टीका लेने वाले व्यक्ति में संभावित साइड इफेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उसने इसे ऐसी संभावित बीमारी बताया है जिसका ब्योरा नहीं है। समाचार साइट एसटीएटी ने सबसे पहले इस परीक्षण को रोके जाने की जानकारी दी।

उसने कहा कि यह साइड इफेक्ट संभवतः ब्रिटेन में सामने आया है। एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ता ने इस टीके के अध्ययन पर अस्थाई रोक की पुष्टि की है। यह अध्ययन अमेरिका और अन्य देशों में चल रहा है। बहरहाल दो अन्य टीकों पर अमेरिका में बड़े पैमाने पर अंतिम चरण का परीक्षण चल रहा है। इसमें एक मोडेरना इंक और दूसरा फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक द्वारा किया जा रहा है। ये दोनों टीके अलग तरह से काम कर रहे हैं और इनके अध्ययन के तहत दो तिहाई के करीब स्वैच्छिक रूप से परीक्षण टीका लेने वालों को शामिल कर लिया गया है। बहरहाल, एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि अस्थाई तौर पर अध्ययन को रोका जाना चिकित्सा क्षेत्र में कोई नई बात नहीं है। किसी तरह की गंभीर अथवा अप्रत्याशित प्रतिक्रिया की जांच करना सुरक्षा परीक्षण का अनिवार्य हिस्सा है। हो सकता है कि यह समस्या एक संयोग हो। अध्ययन एवं परीक्षण के दौरान इस तरह की बीमारी आ सकती है।

नए अध्ययन में हुआ खुलासा

बादाम खाने से मानसिक तनाव की स्थिति में हृदय और तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया में सुधार

इंदौर। एजेंसी

यूके अध्ययन में सामान्य स्नैक्स की जगह बादाम खाने वाले प्रतिभागियों में मानसिक तनाव की स्थिति में प्रतिक्रिया के तौर पर हृदय गति परिवर्तनशीलता में सुधार पाया गया है। मानसिक तनाव उन मनो-सामाजिक कारकों में से एक माना जाता है जोकार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ (सीवीडी) यानि हृदय और रक्तवाहिकाओं संबंधी रोग के खतरों के लिए कारण बनता है। हृदय गति परिवर्तनशीलता (एचआरवी), लगातार हृदय धड़कनों के बीच समय के अंतराल में परिवर्तन का मापन, तनाव के प्रति कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली के रेस्पॉन्स का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और ऐसा माना जाता है कि शारीरिक गतिविधि और आहार सहित जीवनशैली के कारक एचआरवी पर प्रभाव डाल सकते हैं। उच्च एचआरवी पर्यावरणीय और मानसिक चुनौतियों के प्रति रेस्पॉन्स के मामले में हृदय की ज़्यादा अच्छी अनुकूलन क्षमता दर्शाता है, जबकि कम एचआरवी का संबंध कार्डियोवैस्कुलर रोगों और सडन कार्डिएक डेथ यानि अचानक हृदय की धड़कन रुक जाना और हृदय कार्य करना बंद हो जाने से होनेवाली मृत्यु से है।

हाल ही में किए गए क्लिनिकल ट्रायल के एक भाग के अंतर्गत किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने मानसिक तनाव चुनौती से गुज़र रहे प्रतिभागियों में एचआरवी का मापन किया और पाया कि जिन प्रतिभागियों ने छह सप्ताह की अवधि में सामान्य स्नैक्स की जगह बादाम का सेवन किया उनके एचआरवी में सुधार देखा गया। इस अध्ययन का वित्तस पोषण आमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा कियागया था। शोध का यह नया निष्कर्ष एटीटीआईएस अध्ययनका एक हिस्सा था, 6 सप्ताह का एक रैन्डमाइज्ड कंट्रोल, पैरलल-आर्म ट्रायल, जहाँ औसत के ऊपर कार्डियोवैस्कुलर रोग के खतरे वाले प्रतिभागियों ने रोज़ाना स्नैक्स के तौर पर बादाम का या कैलोरी का मेल करते हुए कंट्रोल स्नैक्स का सेवन किया, जिससे प्रत्येक प्रतिभागियों को अनुमानित रोज़ाना ऊर्जा ज़रूरतों का 20इ उपलब्ध कराया गया।

इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों के आराम की स्थिति में (5 मिनट की अवधि के लिए लेटना) और मानसिक तनाव की छोटी अवधि की उत्तेजना के लिए स्ट्रूप टेस्ट के दौरान (जिसमें प्रतिभागियों को कलर किए गए शब्दों को पढ़ने के लिए कहा गया उदाहरण के लिए ग्रीन फॉन्ट में रेड) रियल टाइम हार्ट रेट (एचआर) और हार्ट रेट वैरिएबिलिटी (एचआरवी) को मापा गया।

अत्यधिक मानसिक तनाव के दौरान बादाम ग्रुप वाले प्रतिभागियों में कंट्रोल ग्रुप वालों की तुलना में हृदय गति का नियंत्रण बेहतर पाया गया। इसे हाई फ्रिक्वेन्सी पॉवर में आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर द्वारा दर्शाया गया जो विशिष्ट रूप से प्रत्येक धड़कन के अंतराल का (एचआरवी का मापन) मूल्यांकन करता है।

डॉ. वेन्डी हॉल, पीएचडी, को-प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर (डॉ. सारा बेरी, पीएचडी, के साथ) और किंग्स कॉलेज लंदन में न्यूट्रीशनल साइंसेस में रीडर ने कहा, 'यह अध्ययन दर्शाता है कि सामान्य स्नैक्स की जगह बादाम के आहार में अदला-बदली की साधारण रणनीति से हृदय गति के नियंत्रण में सुधार लाकर मानसिक तनाव के प्रतिकूल कार्डियोवैस्कुलर परिणामों के प्रति लचीलेपन में वृद्धि आ सकती है। हमने पाया कि आहार में हस्तक्षेप के बाद कंट्रोल की तुलना में बादाम का सेवन करने वाले समूह में मानसिक तनाव के कारण होनेवाली हृदय गति परिवर्तनशीलता में कमी आई, जो एक कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य फायदे की ओर संकेत करता है। उच्च एचआरवी के बारे में सोचना उपयोगी हो सकता है क्योंकि इससे शरीर की माँग के अनुसार हृदय तेजी से गियर बदल सकता है जिसका मतलब यह है कि मानसिक तनाव की अवधि के दौरान ज़्यादा कार्डिएक लचीलापन। लंबे समय में यह कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।'

डॉ. सारा बेरी, पीएचडी, किंग्स कॉलेज लंदन ने कहा, ' ऐसे समय में जब हम तनाव के बढ़े हुए स्तर का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही घर से काम करते हुए ज़्यादा स्नैक्स का सेवन कर रहे हैं, ये नतीजे खास तौर पर सही समय पर आए हैं। '

इस अध्ययन के बारे में मैक्स हेल्थकेयर – दिल्ली की रीजनल हेड-डायटेटिक्स रितिका समद्दर ने कहा, 'इस अध्ययन के नतीजे लाभदायक हैं, खासतौर पर भारत जैसे देश के लिए जहाँ मानसिक तनाव और कार्डियोवैस्कुलर रोग (सीवीडी) बड़ी चिंता का विषय हैं। इस नए अध्ययन के नतीजे यह दर्शाते हैं कि किस तरह सामान्य स्नैक्स की जगह नियमित बादाम खा रहे प्रतिभागियों में मानसिक तनाव के प्रति रेस्पॉन्स में हृदय गति परिवर्तनशीलता में सुधार आया। इसलिए मैं बहुत ज़ोर देकर यह सिफारिश करती हूँ कि हाई कैलोरीयुक्त जंक फूड की जगह बादाम खाएं जो स्नैक्स का एक सेहतमंद और पौष्टिकविकल्प है। लंबे समय में यह आसान बदलाव किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण हृदय स्वास्थ्य के लिए भी सहायता करेगा।'

हृदय स्वास्थ्य पर वर्षों के शोध – जिसमें सुव्यवस्थित समीक्षा और मेटा-एनालिसिस शामिल हैं- हृदय के लिए सेहतमंद आहार योजना में बादाम को शामिल करने का समर्थन करते हैं। दोनों ही एटीटीआईएस अध्ययनों में बादाम सहित ऐसे उपायों को शामिल किया गया था जिनका इससे पहले कभी भी क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल्स में मूल्यांकन नहीं किया गया। हालाँकि इन निष्कर्षों की पुष्टि के लिए अतिरिक्त अध्ययनों की आवश्यकता है, लेकिन एचआरवी और एफएमडी में सुधार यह दर्शाते हैं कि बादाम के सेवन से विभिन्न तरह के स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध होते हैं। बादाम फाइबर (12.5 / 3.5 ग्राम प्रति 100ग्राम / 28ग्रामसर्विंग) और 15 आवश्येक पोषक तत्वप मुहैया कराते हैं जिसमें (प्रति 100ग्राम / 28ग्राम सर्विंग): मैग्नीहशियम(270 / 76 एमजी), पोटेशियम(733 / 205 एमजी), और विटामिन ई (25.6 / 7.2 एमजी)शामिल हैं।

रेटिंग एजेंसियों ने अर्थव्यवस्था पर दी एक और टेंशन 15 फीसदी तक गिरावट का अनुमान

मुंबई। एजेंसी

दुनिया की कई रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन साक्स ने वित्त वर्ष 2020- 21 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सबसे ज्यादा 14.8 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं फिच ने 10.5 प्रतिशत और इंडिया रेटिंग एजेंसी ने वर्ष के दौरान जीडीपी का आकार 11.8 प्रतिशत घटने का अनुमान व्यक्त किया है। फिच रेटिंग्स ने वर्ष 2020 में विश्व अर्थव्यस्था में 4.4 प्रतिशत संकुचन का अनुमान जताया है।

एजेंसी के अनुसार चीन का जीडीपी इस साल बढ़ेगा और उसकी आर्थिक वृद्धि दर 2.7 तक रह सकती है। गोल्डमैन साक्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में अपने पहले अनुमान में बड़ी कटौती करते हुये कहा कि 2020- 21 में भारत की जीडीपी में 14.8 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आयेगी। उसने इससे पहले 11.8 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान लगाया था। ब्रोकरेज कंपनी का ताजा अनुमान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े जारी होने के कुछ ही दिन बाद सामने आया है। जीडीपी के अगस्त अंत में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून 2020 तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 23.9 प्रतिशत

घटा है। इस दौरान लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र को छोड़कर ज्यादातर गतिविधियां नीचे आ गईं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में वृद्धि की राह पर लौटाने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वित्त वर्ष में 10.5 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आ सकती है। फिच ने अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (जीईओ) में कहा है, आर्थिक गतिविधियों के शुरू होने पर जीडीपी चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर- दिसंबर 2020) में पटरी पर लौटेगी, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि सुधार की गति धीमी और असमान है।''

फिच ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी के अपने अनुमान को संशोधित करते हुये (-) पांच प्रतिशत अंक के भारी संशोधन के साथ 10.5 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। उसने कहा कि उसके बाद 2021-22 में अर्थव्यवस्था में 11 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। ऐसा इस साल के गिरे आधार की वजह से होगा जबकि उससे अगल साल इसमें 6 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि होगी। फिच की भारतीय इकाई इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसर्च ने 2020- 21 में 11.8 प्रतिशत गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। इससे पहले उसने इस वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी में 5.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वित्त वर्ष 2019- 20 में 4.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी। देश में करीब दो महीने लंबे चले लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई और दूसरी तरफ कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों पर भी अंकुश नहीं लग पाया। कोविड- 19 से संक्रमित लोगों की संख्या 42 लाख से ऊपर निकल चुकी है और 70 हजार से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। गोल्डमैन साक्स के विश्लेषकों का मानना है कि सितंबर 2020 में समाप्त होने वाली दूसरी तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी में 13.7 प्रतिशत, उसके बाद दिसंबर तिमाही में 9.8 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान है।

इससे पहले इन तिमाहियों में क्रमशः 10.7 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया था। वहीं इंडिया रेटिंग्स ने दूसरी तिमाही में 11.9 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.4 प्रतिशत गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। वर्ष 2020- 21 में भारत के जीडीपी में 14.8 प्रतिशत गिरावट आने का गोल्डमैन साक्स का यह अनुमान अब तक व्यक्त किये गये सभी अनुमानों में सबसे निराशाजनक है।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त ने कहा,

एपीआई का उत्पादन बढ़ा रहा है भारत

वाशिंगटन। एजेंसी

जेनेरिक दवाओं के वैश्विक केंद्र भारत ने एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इंग्रिडिएंट (एपीआई) का उत्पादन बढ़ाने की नई योजना शुरू की है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कान्त ने यह जानकारी दी। कान्त ने 14वें वार्षिक जैवऔषध एवं स्वास्थ्य सेवा शिखर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक एपीआई के लिए भारत काफी हद तक चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर करता था। उन्होंने कहा कि भारत अब फार्मास्युटिकिल पारिस्थितिकी तंत्र में नवोन्मेषण के लिए तैयार हो रहा है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि भारत ने एपीआई का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की। अभी तक भारत इसके लिए काफी हद तक चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर था। यूएस-इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा शुक्रवार को आयोजित वर्चुअल शिखर बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ''हम भारत में पूर्ण विनिर्माण की योजना बना रहे हैं।'' दिनभर चली इस वर्चुअल बैठक में अमेरिका के फार्मा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां शामिल हुईं। इन कंपनियों का शोध एवं विकास का सामूहिक सालाना बजट 45 अरब डॉलर है। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से अमेरिका और चीन के संबंध काफी खराब हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनियाभर में वायरस फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। अब तक इस महामारी से दुनियाभर में आठ लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कान्त ने कहा कि भारत सरकार अपने 'फार्मा दृष्टिकोण 2020' को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके जरिये भारत को दवा खोज, नवोन्मेषण और औषधि विनिर्माण में दुनिया का अग्रणी देश बनाने का लक्ष्य है।

सर्वपितृ अमावस्या पर पूजें इन 4 पितृ देवों को, तभी होंगे पितृ तृप्त

श्राद्ध पक्ष में पितरों के देव और देवताओं को पूजने से सभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण, पिंडदान आदि करते वक्त प्रमुख रूप से चार पितृदेवों का आह्वान किया जाता है। कौन है ये चार पितृ आओ जानते हैं इनके नाम।

पुराण अनुसार मुख्यतः पितरों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है- दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है, जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए, इसका निर्णय करता है। इस जमात का प्रधान यमराज है और उनके सहयोगी चित्रगुप्त है। परंतु इसके अलावा पितरों के देव भी हैं।

1.दिव्य पितर की जमात के सदस्यगण : अग्निष्वात्त, बर्हिषद आज्यप, सोमेप, रश्मिप, उपदूत, आयन्तुन, श्राद्धभुक व नान्दीमुख ये नौ दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी केवल नांदीमुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं।

2. अर्यमा : ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में से एक अर्यमन हैं। ये बारह हैं:- अंशुमान, इंद्र, अर्यमन, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम (वामन)।

अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर-देवताओं में से एक अर्यमन या अर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाशगंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार प्रातः और रात्रि के चक्र पर है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में अर्यमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन-सा पितृत किस कुल और परिवार से है। पुराण अनुसार उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है।

3. चार व्यवस्थापक : यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्यवाडनल, सोम, अर्यमा और यम- ये चार इस जमात के मुख्य गण प्रधान हैं। अर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश।

इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, यथा- अग्निष्व, देवताओं के प्रतिनिधि, सोमसद या सोमपा- साध्यों के प्रतिनिधि तथा बर्हिषद- गंधर्व, राक्षस, किन्नर सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सबसे गठित जो जमात है, वही पितर हैं। यही मृत्यु के बाद न्याय करती है।

श्राद्ध के समय इनके नाम से जलदान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र सूर्य तथा वरुण जल देवता के साथ स्वाहा का 'हव्य' और श्राद्ध में स्वधा का 'कव्य' दोनों स्वीकार करते हैं। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है।

सूर्य किरण का नाम अर्यमा : देसी महीनों के हिसाब से सूर्य के नाम हैं- चैत्र मास में धाता, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भाद्रपद में विवस्वान, आश्विन में पूषा, कार्तिक में पर्जन्य, मार्गशीर्ष में अंशु, पौष में भग, माघ में त्वष्टा एवं फाल्गुन में विष्णु। इन नामों का स्मरण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है।

श्राद्ध या तर्पण : पितृ पक्ष में तीन पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा तीन पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है।

पितर चाहे किसी भी योनि में हों वे अपने पुत्र, पुत्रियों एवं पौत्रों के द्वारा किया गया श्राद्ध का अंश स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण पुष्ट होते हैं और उन्हें नीच योनियों से मुक्ति भी मिलती है। यह कर्म कुल के लिए कल्याणकारी है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर चले जाते हैं। पूरे वर्ष वे लोग उनके श्राप से दुखी रहते हैं। पितरों को दुखी करके कौन सुखी रह सकता है? श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्म, गरूड़, विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में यथास्थान किया गया है।

अत्यंत दुर्लभ व शुभ होता है श्राद्ध में 'गजच्छाया योग'

शास्त्र का वचन है- 'श्रद्धया इदं श्राद्धम'

अर्थात् श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के निमित्त किया गया कर्म ही श्राद्ध है। प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष (महालय) भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहता है। इस अवधि में सनातनधर्मी अपने पितरों के निमित्त श्राद्धकर्म करते हैं। श्राद्ध के लिए गया, पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार व ब्रह्मकपाली (बद्रीनाथ) आदि तीर्थों का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त किसी पवित्र नदी के तट पर भी श्राद्ध करने का विधान शास्त्रों में निर्देशित है। श्राद्ध कर्म करने के लिए महालय अर्थात श्राद्ध पक्ष ही सर्वोत्तम है किंतु यदि श्राद्ध पक्ष में 'गजच्छाया-योग' मिल जाए तो यह अत्यंत ही उत्तम व सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन जाता है। श्राद्ध पक्ष के अतिरिक्त भी यदि 'गजच्छाया योग' मिले तो उसमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। 'गजच्छाया योग' अत्यंत दुर्लभ होता है व कई वर्षों के उपरांत बनता है। इस योग में श्राद्ध करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों को सद्गति मिलती है। कब बनता है 'गजच्छाया योग'- जिस दिन त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र हो एवं सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो उस दिन 'गजच्छाया-योग' का निर्माण होता है। 'गजच्छाया योग' में श्राद्ध करने से अनंत पुण्य मिलता है। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष में यह योग नहीं बन रहा है।

पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी 13 सितंबर 2020 को

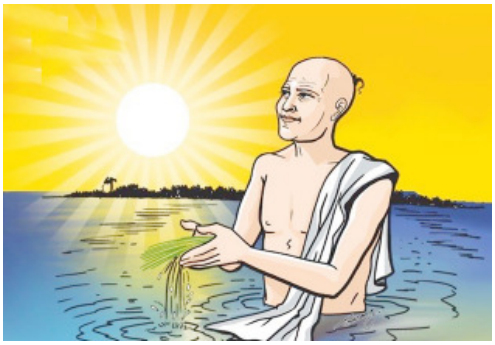

इस वर्ष अधिकमास होने से 24 की जगह 26 एकादशियां होगी। माह में 2 एकादशियां होती हैं अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियमपूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिकमास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं।

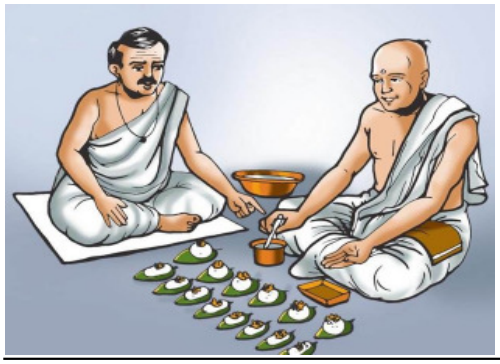

इंदिरा एकादश

आश्विन माह में इंदिरा एवं पापांकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है जबकि पापांकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इंदिरा एकादशी के दिन विधिवत रूप से व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और वे नया जीवन प्राप्त करते हैं।

इंदिरा एकादशी शुभ मुहूर्त

एकादशी तिथि 13 सितंबर 2020 को सुबह 4 बजकर 13 मिनट से प्रारंभ होकर 14 सितंबर 2020 सुबह 03 बजकर 16 मिनट तक पर समाप्त होगी। इंदिरा एकादशी व्रत पारण 14 सितंबर को दोपहर 01:30 से दोपहर 03:59 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी व्रत कथा :सतयुग में विष्णु का परम भक्त इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी महिष्मति नाम के राज्य पर राज्य करता था। महिष्मति राज्य में जनता सुखपूर्वक रहती थी। एक दिन नारदजी इंद्रसेन के दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने राजा को उनके मृत पिता के यमलोक में होने की बात बताई। पूर्व जन्म में उनसे कोई गलती हो गई थी जिस कारण वे यमलोक में हैं। नारद ने राजा को उपाय बताते हुए कहा कि यदि इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखें तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा ने नारदजी से इंदिरा एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से जानने की जिज्ञासा प्रकट की तो नारदजी ने कहा कि एकादशी तिथि से पूर्व दशमी को विधि-विधान से पितरों का श्राद्ध करें और एकादशी की तिथि को व्रत रखें और द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के बाद दान आदि का कार्य करने के बाद व्रत का पारण करें। राजा इंद्रसेन ने नारद के बताए हुए नियमों के अनुसार ही व्रत किया। एकादशी का व्रत रखने के कारण उनके पिता को स्वर्ग प्राप्त हुआ।

पितृ अमावस्या के एक माह बाद नवदुर्गा उत्सव 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास रहेगा

17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शुद्ध अश्विन माह होंगे

इस साल 17 अक्टूबर से दुर्गा पूजा की शुरूआत होगी। विजयादशमी 26 अक्टूबर को है। सभी 10 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाएगी। हर साल पितृ पक्ष के समापन के अगले दिन से नवरात्र की शुरूआत होती। इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही अधिकमास लगने वाला है। मलमास लगने से नवरात्र और पितृपक्ष के बीच एक महीने का अंतर आ जाएगा। इस संबंध में डॉ. अशोक शास्त्री ने बताया कि 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास रहेगा। 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शुद्ध अश्विन माह होंगे। इस दौरान ही 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक मां दुर्गा की पूजा की जाएगी। उन्होंने बताया कि पितृपक्ष तीन सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक शुद्ध आश्विन मास में चलेगा। उसके 30 दिनों के बाद मां दुर्गा की पूजा होगी। उन्होंने बताया कि सूर्य मास और चंद्रमा मास गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है। जो 32 माह 16 दिन आठ घंटे के अंतर से मलमास का निर्माण होता है। सूर्य वर्ष 365 दिन छह घंटे का होता है तथा चंद्र वर्ष 354 का माना जाता है। 165 साल बाद बना संयोग, आश्विन मास में मलमास ज्योतिषाचार्य डॉ. अशोक शास्त्री के अनुसार आश्विन मास में मलमास लगना और एक महीने के अंतर पर दुर्गा पूजा आरंभ होना ऐसा संयोग करीब 165 साल बाद लगने जा रहा। ज्योतिष में बताया जाता है कि लीप वर्ष होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए इस बार चातुर्मास जो हमेशा चार महीने का होता है। इस बार पांच महीने का होगा। ज्योतिषाचार्य डॉ. अशोक शास्त्री के मुताबिक 160 साल बाद लीप ईयर और अधिकमास दोनों ही एक साल में हो रहे है। चातुर्मास लगने से विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इस काल में पूजन पाठ, व्रत उपवास और साधना का विशेष महत्व होता है। इस दौरान देव सो जाते है।

देश की प्रथम जैतून रिफाइनरी में तेल निकालने का काम शुरू, किसानों में खुशी

त्रिभुवन रंगा, बीकानेर। एजेंसी

इजराइल से आई जैतून की फसल तकनीक अब राजस्थान में फल फूल रही है। इनकी बानगी है कि देश की पहली जैतून रिफाइनरी अब अपने पूरे शबाब पर आ गई। जैतून को लेकर किसानों की बढ़ी रुचि ने रिफाइनरी को एक नया जीवनदान दिया। राजस्थान में जैतून का नाम लेने पर ही ऐसा लगता था कि ये कौन सा फल है? उसके बाद उसकी खेती करना जैसे कोई काल्पनिक कहानी हो। कुछ ऐसा ही बीकानेर के लूणकरणसर में देखा जा रहा है। जी है जिस फसल की कुछ वर्षों पूर्व कल्पना नहीं की जा रही है, आज उसकी रिफाइनरी सफलता के झंडे गाड़ रही है। देश की पहली रिफाइनरी में राजस्थान भर के किसान अपनी फसल को लेकर इस रिफाइनरी में आयल निकाल रहे हैं। लूणकरणसर में स्थित देश की प्रथम जैतून रिफाइनरी में इस सेशन का एक्सट्रेशन कार्य शुरू हो चुका। इस सीजन के जैतून फल पूरी पककर तैयार हो चुके और किसान राज्य भर से लूणकरणसर स्थित जैतून रिफाइनरी में फसल लेकर पहुंचने लगे हैं।

जैतून की खेती किसानों की पहली पसंद बनती जा रही

इजरायल से इम्पोर्ट किये गए जैतून की फसल की तरफ राजस्थान के किसान काफी आकर्षित नजर आ रहे हैं। शुरुआती दौर में किसानों ने जैतून की खेती को ज्यादा महत्व नहीं दिया था परंतु मौजूदा समय में जैतून की खेती किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। अब राजस्थान भर के किसान जैतून की खेती करने लगे है। जैतून खेती से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यह जैतून के पेड़ लगाने के पांच साल के बाद फल देना शुरू कर देते हैं। इन पांच सालों में इनकी दो से तीन बार कटाई की जाती है, जिससे इनकी ग्रोथ रेट बढ़ती है। जैतून का तैल (ऑलिव ऑयल) खाने और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में काम लिए जाते हैं। इसके साथ ही इनकी टहनियों में भी तेल की मात्रा होती है, जो कटाई के बाद जलाने के काम आती है। वहीं जानकारों का कहना है कि इसकी पत्तियों को सुखाकर चाय भी बनाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है।

राजस्थान में जैतून की बहुत ही शानदार पैदावार

रिफाइनरी प्रबंधक सीताराम यादव ने बताया कि सरकार ने इजरायल से जैतून की सात किस्में इम्पोर्ट की है, जिनमें से पांच की राजस्थान में बहुत ही शानदार पैदावार हो रही है. वहीं सरकार के 182 हेक्टेयर में जैतून के फार्म लगे हुए हैं। तो वहीं राजस्थान में किसानों द्वारा एक हजार हेक्टेयर में जैतून की खेती की जा रही है। झुंझुनूं से अपनी फसल का आयल निकालने आए किसान कहते है कि पहले इस खेती को लेकर किसानों में ज्यादा उत्साह नही था लेकिन अब इससे होने वाले आर्थिक लाभ से किसान प्रेरित हो रहे। जैतून को लेकर किसानों की बढ़ी रुचि से कहा जा सकता कि वो दिन दूर नही जब राजस्थान इजरायल की बराबरी कर लेगा। जिस तरह से जैतून के पेड़ का हर पार्ट उपयोगी है, किसान के लिए जैतून की खेती काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।

रॉयल एनफील्ड अर्जेंटीना में शुरू करेगी मोटरसाइकिल की असेंबलिंग

नयी दिल्ली। एजेंसी

रॉयल एनफील्ड अर्जेंटीना में अपनी मोटरसाइकिल असेंबलिंग शुरू करेगी। इसके लिए कंपनी ने 'ग्रुप सिंपा' से गठजोड़ किया है जो 2018 से वहां उसकी स्थानीय वितरक कंपनी है। आयशर मोटर्स की दोपहिया वाहन इकाई ने एक बयान में कहा कि रॉयल एनफील्ड के आधुनिक इतिहास में यह पहली बार होगा जब कंपनी की मोटरसाइकिल का उत्पादन और असेंबलिंग उसके चेन्नई संयंत्र से इतर कहीं होगी। कंपनी की स्थानीय असेंबलिंग ग्रुप सिंपा के ब्यूनो आयरीज स्थित कंपाना संयंत्र में की जाएगी। रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद के. दसारी ने कहा, " इस महीने में कंपनी पहले रॉयल एनफील्ड हिमालयन, इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटर जीटी 650 की स्थानीय असेंबलिंग शुरू करेगी।" उन्होंने कहा कि कंपनी नियमित तरीके से मध्यम श्रेणी की मोटरसाइकिल के वैश्विक बाजार विस्तार पर काम कर रही है। साथ ही वैश्विक बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ा रही है। मौजूदा समय में कंपनी 60 से अधिक देशों में अपने उत्पाद पहुंचाती है।

जेएसडब्ल्यू स्टील का उत्पादन अगस्त में पांच प्रतिशत बढ़कर 13.17 लाख टन रहा

नयी दिल्ली। एजेंसी

जेएसडब्ल्यू स्टील ने बुधवार को कहा कि अगस्त 2020 में उसका इस्पात उत्पादन पांच प्रतिशत बढ़कर 13.17 लाख टन तक पहुंच गया। एक साल पहले इसी माह के दौरान कंपनी ने 12.53 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया था। कंपनी के जारी वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि माह-दर- माह के आधार पर जेएसडब्ल्यू स्टील का उत्पादन एक महीना पहले जुलाई के 12.46 लाख टन के मुकाबले अगस्त में छह प्रतिशत बढ़कर 13.17 लाख टन पर पहुंच गया। समीक्षागत माह (अगस्त 2020) के दौरान इस्पात चादरों का उत्पादन पिछले साल अगस्त के उत्पादन के मुकाबले 15 प्रतिशत बढ़कर 9.80 लाख टन पर पहुंच गया। वहीं जुलाई के मुकाबले इसमें चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, अगस्त 2020 में लंबी तारों के ढेलों का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत घटकर 2.32 लाख टन ही रहा। वहीं एक माह के पहले के मुकाबले इसमें तीन प्रतिशत की गिरावट रही। जेएसडब्ल्यू स्टील, 12 अरब डालर के जेएसडब्ल्यू समूह की अग्रणी कंपनी है। समूह का कारोबार इस्पात, ऊर्जा, अवसंरचना, सीमेंट और खेल कूद सामान के क्षेत्र में फैला है।

मलेशिया और शिकॉगो एक्सचेंज में तेजी से पाम, सोयाबीन तेल कीमतों में सुधर

नयी दिल्ली। एजेंसी

मलेशिया और शिकॉगो एक्सचेंज में 2.5 - 2.5 प्रतिशत की तेजी के कारण स्थानीय तेल-तिलहन बाजार में मंगलवार को पाम एवं पामोलीन तथा सोयाबीन तेल कीमतों में सुधार का रुख रहा और इनके भाव लाभ दर्शाते बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि शिकॉगो एक्सचेंज में तेजी के कारण सोयाबीन तेल कीमतों में सुधार आया मगर सस्ते आयात के आगे मांग कमजोर होने से सोयाबीन दाना के भाव में गिरावट आई। इसी प्रकार सस्ते आयातित तेलों की बाढ़ के आगे देशी तिलहनों के पांव ठिठक गये जिसकी वजह से मूंगफली दाना, सोयाबीन दाना के भाव में गिरावट रही। सरसों दाना के भाव भी सस्ते आयात के कारण मामूली कमजोर रहे। वैसे सरसों की स्थिति अन्य तेल-तिलहनों के मुकाबले बेहतर है और सहकारी संस्था-नाफेड आगामी फसल के आने में सात-आठ महीने की देरी के कारण मांग होने के बावजूद सोच समझकर कम मात्रा में बिकवाली कर रही है। सूत्रों ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में आत्मनिर्भरता की हिमायती है, तो उसे सस्ते आयातित तेलों पर अंकुश लगाते हुए उसपर शुल्क बढ़ा देना चाहिये। उन्होंने कहा कि अपनी जरूरत के 70 प्रतिशत खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भर करने वाले देश भारत में देशी किसानों की अपनी लगभग 25 प्रतिशत उपज बाजार में खप नहीं पाती है। इसे खपाने के लिए सस्ते आयातित तेलों पर आयात शुल्क को बढ़ाना चाहिये। तभी यहां के तिलहन उत्पादक किसान लाभान्वित और उत्साहित होंगे और उत्पादन बढ़ाने को प्रेरित होंगे। सूत्रों ने कहा कि जब पैदावार बढ़ती है तो सस्ते आयात के कारण किसानों के लिए अपने माल को बाजार में खपाना मुश्किल हो जाता है। बाजार का हाल यह है कि वायदा कारोबार में सोयाबीन के नवंबर अनुबंध का भाव 3,822 रुपये क्विन्टल चल रहा है जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 3,880 रुपये क्विन्टल (मंडी शुल्क, वारदाना सहित सारे खर्चे अलग से) है।

5जी प्रौद्योगिकी पर मिलकर काम कर रहे हैं, भारत, अमेरिका, इस्राइल : अधिकारी

वाशिंगटन। एजेंसी

भारत, इस्राइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि तीनों देश 5जी संचार नेटवर्क पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि तीनों देश एक पारदर्शी, खुले, विश्वसनीय और सुरक्षित 5जी संचार नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। सामुदायिक नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन साल पहले जुलाई, 2017 की इस्राइल यात्रा के दौरान लोगों-से-लोगों के संपर्क पर सहमति बनी थी। विकास वाले और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है। अंतराष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी (यूएसएआईडी) की उप-प्रशासक बोनी ग्लिक ने कहा, "5जी में आपसी सहयोग तो बड़े कदमों की दिशा में सिर्फ पहला कदम है।" ग्लिक ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा, "हम विज्ञान तथा शोध एवं विकास तथा अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में मिलकर काम कर रहे हैं। इस भागीदारी के जरिये हम आधिकारिक तौर पर इन संबंधों की पुष्टि कर रहे हैं।" इससे पहले ग्लिक ने अमेरिका-भारत-इस्राइल के बीच वर्चुअल शिखर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम दुनिया की विकास से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए इन भागीदारों के साथ काम कर काफी रोमांचित हैं। इस बैठक को भारत में इस्राइल के राजदूत रॉन मलका तथा उनके समकक्ष संजीव सिंगला ने भी संबोधित किया। ग्लिक ने कहा, "जिस एक क्षेत्र में हम सहयोग कर रहे हैं वह है डिजिटल नेतृत्व तथा नवोन्मेषण। विशेषरूप से हमारा सहयोग अगली पीढ़ी की 5जी प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है।"

ऊषा इंटरनेशनल ने लगातार सातवें साल मुंबई इंडियंस से साझेदारी जारी रखी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

सितंबर 2020: भारत की प्रमुख कंज्यूमर ड्यूरेबल्सस कंपनियों में से एक, ऊषा इंटरनेशनल ने मुंबई इंडियंस टीम से लगातार सातवें साल ऑफिशियल पार्टनर के रूप में अपनी साझेदारी बरकरार रखी है। सितंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू हो रहे टूर्नामेंट का 13वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में तीन जगहों, शारजाह, अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। इस साझेदारी के हिस्से के तौर पर ऊषा का लोगो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों की कैप के आगे और हेलमेट पर देखा जाएगा। इसके साथ ही मैच टॉस के दौरान मैट पर भी ये लोगो बना देखा जा सकेगा। इस वर्ष ऑनलाइन और टीवी दर्शकों की तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टेडियम को विभिन्न सुविधाओं से लैस किया गया है। स्टेडियम में एक निश्चित लंबाई और चौड़ाई में विशाल एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। इस स्क्रीन पर कुछ ओवर का गेम पूरा होने के बाद ऊषा ब्रैंड के विज्ञापन दिखाए जाएंगे।

आज जब जगह-जगह पर कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा निर्देश लागू हैं। क्रिकेट के इस सीजन का मकसद लोगों को वर्चुअल अहसास दिलाना है। ऊषा ने हितधारकों के बढ़ते जुड़ाव को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई एक्टिवेशन सीरीज की योजना बनाई है। इसके अलावा जिस दिन मुंबई इंडियंस की टीम खेल रही होगी, कंपनी ब्रैंड रिकॉल-ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी आयोजित करेगी, जिसमें उपभोक्ताओं को मुंबई इंडियंस टीम के अपने मनपसंद खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल ढंग से मिलने और बातचीत का मौका दिया जाएगा। ऊषा इंटरनेशनल के सीईओ श्री दिनेश छाबड़ा ने कहा, 'किसी भी संबंध की ताकत उसकी लंबी आयु और मुश्किल वक्त में मजबूती से झलकती है। आज इस मुश्किल समय में भी हमारी मुंबई इंडियंस के साथ साझेदारी इस रिश्ते की ताकत का सबूत है। किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की तरह स्पोर्ट्स पर भी इस महामारी के प्रकोप का काफी असर पड़ा है। हमें विश्वास है कि इतने बड़े गैप के बाद भारतीय क्रिकेट का पहला लाइव क्रिकेट इवेंट होने के नाते दुनिया भर में इसे भारी तादाद में दर्शक देखेंगे। इससे इस इवेंट की व्यूअरशिप रॉकेट की तरह आसमान पर पहुंचेगी। इन मैचों को दुनिया में क्रिकेट के हर फैन और हर घर तक पहुंचाने के लिए इन मैचों का लाइव प्रसारण अलग-अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। मुंबई इंडियंस से हमारी साझेदारी से, हमें एयर और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अलग-अलग श्रेणियों में ग्राहकों और भागीदारों के साथ संबंध मजबूत करने का मौका मिला है। यह साझेदारी ऊषा ब्रैंड के मूल्यों से पूरी तरह तालमेल रखती है और इससे खेल और एक्टिव व हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के कंपनी के मूल्यों की झलक मिलती है। घर पर सक्रिय रहने और घर में बना ताजा भोजन करने से इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जो आज के माहौल में किसी भी चीज से ऊपर है।

झीलों की नगरी के प्रसिद्ध लकड़ी के खिलौनों को खा गया चीन

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' से फिर जगी उम्मीद

उदयपुर। एजेंसी

झीलों की नगरी उदयपुर अपनी कला के लिये भी दुनिया में मशहूर है। हालांकि अब अधिकांश कलाएं (Arts) दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन इन कलाओं को जीवंत रखने की कोशिश अभी भी जारी है। उदयपुर की ऐसी ही एक कला थी लकड़ी के खिलौनों (Wooden toys) को बनाने की। बताया जाता है कि करीब 170 साल पहले देश में लकड़ी के खिलौने बनाने का व्यापार सबसे पहले उदयपुर में शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे यह व्यापार देश के कुछ अन्य शहरों में भी फैला। बाद में स्थानीय परिस्थितियों और चीनी खिलौने के बढ़ते प्रभाव से यह कला दम तोड़ गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर देश में बने खिलौने के प्रोत्साहन की बात कहकर इन कारीगरों के मन के उत्साह को जीवित कर दिया है।

उदयपुर में बने लकड़ी के खिलौनों की डिमांड पूरे देश में रहती थी

पहले उदयपुर में बने लकड़ी के खिलौनों की डिमांड पूरे देश में रहती थी। उदयपुर लकड़ी के खिलौना का बहुत बड़ा केन्द्र हुआ करता था। यहां घर- घर में खिलौने बनाने की मशीनरी लगी हुई थी। इससे जुड़े लोग दिन-रात खिलौने बनाने के कार्य में जुटे रहते फिर भी मांग के अनुरुप सप्लाई करना मुश्किल रहता था। उदयपुर के खेरादीवाड़ा में हर घर में लकड़ी के खिलौने बनाये जाते थे। करीब 600 लोग इस कारोबार से अपना गुजर बसर करते थे। बताया जाता है कि 1960 के दशक तक उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाने के 170 कारखाने हुआ करते थे। यह खिलौने विदेशी मेहमानों का भी मन मोह लेते थे। लेकिन चीनी खिलौनों के बढ़ते प्रचलन के बाद उदयपुर के इस खिलौना कारोबार को चीन की नजर लग गई। धीरे धीरे यह कारोबार और कला इतिहास बनने लगी।

उदयपुर में अब सिर्फ दो ही परिवार बनाते हैं ये खिलौने

करीब 90 के दशक में वन विभाग द्वारा लकड़ी को लेकर बरती गई सख्ती के साथ ही कारीगरों ने इससे हाथ खींच लिये और चीनी खिलौने का चलन देश में बढ़ने लगा। चीनी खिलौने के देश में प्रवेश के साथ ही यह कारोबार भी ठप होने लग गया। चीनी खिलौने के चलन के साथ ही लकड़ी के खिलौने का कारोबार खत्म होने लगा। इसके बाद इससे जुड़े लोगों ने दूसरे कार्य को अपनी आजिविका का साधन बना लिया. ऐसे कारीगर जो अपने हाथ के हुनर से खूबसुरत लकड़ी के खिलौने तैयार करते थे वे ऑटो चलाने, सब्जी बेचने या अन्य किसी दुकान पर कार्य करने के लिये मजबूर हो गये। वर्तमान में उदयपुर में सिर्फ दो परिवार ही हैं जो लकड़ी के खिलौने बनाने का काम करते हैं और वह भी प्री-ऑर्डर मिलने पर।

युवाओं को जोड़ने के लिये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की भी जरुरत

उदयपुर हेंडिक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेन्द्र भंसाली ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत अभियान में खिलौना इंडस्ट्री को जोड़ने के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया है बल्कि इस उद्योग से एक बार फिर युवाओं को जोड़ने के लिये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाने की जरूरत बताई है। केन्द्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत देश के उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही चीनी प्रोडक्ट का चलन देश में कम करने के प्रयास में जुटी है।

जनता व राजनेताओं के बीच की कड़ी को मजबूत करेगा 'ट्रूपल बुंदेलखंड'

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

देश का अग्रणी ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफार्म ट्रूपल डॉट कॉम अब बुंदेलखंड क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। बुंदेलखंड के सभी 13 जिलों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए, चैनल ने बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे बड़े ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क का दर्जा भी प्राप्त कर लिया है। 1 सितम्बर से शुरू हुए सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले 'ट्रूपल बुंदेलखंड' की ख़ास बात यह है कि चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों से जुड़ने का प्रयत्न कर रहा है। जिससे ग्राउंड लेवल की समस्याओं को अधिक स्पष्टता से समझा व समझाया जा सकता है। झाँसी, सागर, कालपी, चिरगांव, दतिया, डबरा, पन्ना, बाँदा, चित्रकूट, टीकमगढ़, ललितपुर, दमोह, जालौन, ओरई, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, अशोकनगर और छतरपुर जैसे शहरों में अपने प्रतिनिधियों के जरिये चैनल बारीक जानकारियों को सटीकता से दर्शाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए चैनल के को फाउंडर अतुल मलिकराम ने बताया कि, 'ट्रूपल बुंदेलखंड के माध्यम से स्थानीय निवासियों की जमीनी समस्याओं को प्रसाशनिक अधिकारियों व सम्बंधित प्रतिनिधियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही समस्या से जुड़े विभागों को उसके निवारण के प्रति कार्य करने में सहूलियत होगी। यह सिर्फ एक चैनल के तौर पर नहीं बल्कि जनता और राजनेताओं के बीच में पुल के रूप में भी कार्य करेगा।'

ट्रूपल डॉट कॉम पिछले लम्बे समय से एक ऐसे डिजिटल प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर रहा है जिसने कृषि, शिक्षा व सामाजिक विषयों के क्षेत्र में अपने विचार खुलकर पेश किये हैं। राजनीतिक विश्लेषण हो या जनप्रतिनिधियों के काम का डिजिटल आकलन, चैनल ने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। पिछले दिनों 15 अगस्त के अवसर पर संस्था ने उज्जैन को प्रसाशन द्वारा पवित्र नगरी घोषित किये जाने को लेकर देश का सबसे बड़ा डिजिटल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस अभियान से अब तक 50 हजार से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। वहीं चैनल ने कोविड काल को ध्यान, पहली बार घुमंतू समाज, श्मशान तथा कब्रिस्तानों की बद्दतर स्थिति पर भी प्रसाशनिक महकमे को जगाने की कोशिश की है। जिससे ऐसे स्थलों का ख़ास ख्याल रखकर, संक्रमण के प्रभाव को कम करने के प्रयास किये जा सके।

पीएमजकेपी से हुई 42 करोड़ लोगों को 68,820 करोड़ रुपये की मदद

नई दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत अब तक 42 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 68,820 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि पीएम-किसान सम्मावन निधि की पहली किश्त के तौर पर 17,891 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिससे 8.94 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। इसी तरह 10,325 करोड़ रुपये की पहली किश्त 20.65 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में डाले गए। दूसरी किश्त के तौर पर 10,315 करोड़ रुपये और तीसरी किश्त के रूप में 10,312 करोड़ रुपये महिलाओं के जनधन खातों में जमा कराए गए। मंत्रालय ने बताया कि 2.81 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यागों के खातों में दो किश्तों में 2,814.5 करोड़ रुपये डाले गए। इसी तरह पीएमजीकेपी के तहत 1.82 करोड़ कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 4,997.18 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। वहीं, ईपीएफओ में 24 फीसदी अंशदान के तहत .43 करोड़ कामगारों को 2476 करोड़ रुपये का फायदा मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में तीन किश्तों में कुल 9700 करोड़ रुपये गरीबों को दिए गए। इस तरह इन योजनाओं से कुल 42.08 करोड़ गरीबों को 68820 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। गौरतलब है कि कोविड-19 की महामारी के दौरान आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी उसी पैकेज का हिस्सा है।

भारत चीन विवाद

NHAI ने चीनी कंपनी को किया अयोग्य घोषित

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत और चीन के बीच बढ़ रही तनातनी के बीच केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने चीन की एक कंपनी को अयोग्य घोषित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर एक निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिरने के मामले वह कंपनी जिम्मेदार पाई गई थी। इसलिए वह कंपनी अब अगले तीन साल तक NHAI की किसी भी परियोजना में भाग नहीं ले सकती है। इसी के साथ तीन अन्य कंसलटेंट को भी डिबार किया गया है।

गंगा पुल दुर्घटना में पाए गए जिम्मेदार

NHAI से मिली सूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एनएच 34 पर फरक्का से रानीगंज के हिस्से को फोर लेन सड़क में बदला जा रहा है। इसी हिस्से में गंगा नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है। उसी पुल पर गार्डर लांचिंग के दौरान बीते 16 फरवरी को दुर्घटना हुई थी और दो लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में पुल के विशेषज्ञों से जांच करायी गई थी। जांच प्रक्रिया में ही चीन की यह कंपनी भी जिम्मेदारी पाई गई।

इन पर गिरी गाज

NHAI के मुताबिक इस परियोजना को कार्यरूप दे रही चीन की कंपनी क्विंगदाओ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड और घरेलू कंपनी आरकेईसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर संयुक्त रूप से भविष्य में किसी परियोजना में भागीदार बनने से रोक लगा दी है। दोनों कंपनियां अलग-अलग या संयुक्त रूप से भी अगले तीन साल तक एनएचएआई की किसी निविदा में बोली नहीं लगा सकेंगी।

कंसलटेंटों पर भी हुई कार्रवाई

इस मामले में वैक्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और नागेश कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी समान तरीके से रोक लगायी गयी है। साथ ही दिल्ली की एनसी इंफ्राकॉन कंसल्टेंट पर तीन साल के लिए बैन है। ये कंपनियां संयुक्त रूप से या अलग अलग टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगी।

क्या थी कमी

इस परियोजना में हुई दुर्घटना के बाद एनएचएआई ने मामले की जांच के लिए एक पुल विशेषज्ञ की नियुक्ति की थी। विशेषज्ञ ने अपनी जांच में घटना का जिम्मेदार ठेकेदार, डिजाइन कंसलटेंट और लॉन्चिंग गार्डर के डिजाइनर के बीच कोओर्डिनेशन की कमी को पाया। जांच में ठेकेदार और कंसलटेंट को डिजाइन और लॉन्चिंग गार्डर प्रणाली में दोष के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जांच के दौरान वह इस असफलता के लिए कोई ठोस कारण पेश नहीं कर सके थे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।